चुनावी बेला में और कितना झूठ बोलोगे खट्टर जी ?

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

संघ से प्राप्त झूठ बोलने की महारत का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। अभी करीब डेढ़ माह पूर्व वे पलवल से सीधे चण्डीगढ़ की रेल लाइन बिछाने जा रहे थे तो अब वे एक और नई रेल लाईन बिछाने का छलावा देने लगे हैं।

पहले तो उन्होंने पलवल-सोहना-मानेसर-गुड़गांवा-गढ़ी हरसरू-फ र्खनगर-झज्जर-रोहतक-गोहाना-पानीपत के रास्ते शताब्दी ट्रेन को चण्डीगढ़ तक ले जाने का शगूफा छोड़ा था। लेकिन दो दिन पूर्व छोड़े गये नये शगूफे के अनुसार वे केएमपी यानी कुंडली-मानेसर-पलवल सड़क के सामान्तर एक रेलवे लाईन बनायेंगे जिससे जनता पलवल से सीधे चण्डीगढ़ पहुंच जायेंगी। इस ड्रामें को विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने अपनी एक रेलवे कार्पोरेशन भी बना ली है। इसका एकमात्र लाभ उन सत्ताधारियों को होने वाला है जिनकी जमीनें केएमपी के आसपास पड़ी हैं। गिरते जमीनों के भाव उठाने के लिए यह शगूफा छोड़ा गया है। वैसे यह कार्पोरेशन बना तो पूर्व सीएम हुड्डा ने ही दी थी, खट्टर ने इसे पुनर्जीवित कर दिया है।

देखने वाली बात यह है कि जिस हरियाणा सरकार से अपनी रोडवेज की बसें तो ठीक प्रकार से चल नहीं पा रही वह सरकार रेलवे महकमे में क्यों घुसना चाह रही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि पलवल से चण्डीगढ़ से शताब्दी जैसी सीधी रेल सेवा होनी चाहिए परन्तु यह काम भाजपा की मोदी सरकार का है न कि खट्टर सरकार का। आज खट्टर यह आरोप लगाने की स्थिति में भी नहीं हैं कि केन्द्र में विरोधी पार्टी की सरकार है, इसलिये वे मजबूर हैं अपनी खुद की रेलवे लाईन बिछाने को। वैसे भी खट्टर बेचारे क्या रेलवे लाईन बिछायेंगे जब उनकी मोदी सरकार से बीते 5

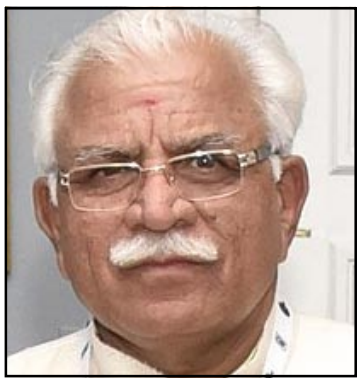

साल में असावटी से बदरपुर के बीच करीब 30 किलोमीटर की लाईन ही नहीं बिछ पाई। विदित है कि करीब 9 वर्ष पूर्व बदरपुर से पलवल तक चार व पलवल से मथुरा तक दो से बढ़ाकर तीन लाईन करने का प्रोजेक्ट चला था।

कांग्रेस सरकार रोते-पीटते अपने शासनकाल में मथुरा से असावटी तक की लाईन तो बना गयी परन्तु मोदी जी की तीव्र गति से चलने वाली सरकार इस लाईन को केवल असावटी से बल्लभगढ़ तक ही ला पाई। और तो और ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बीते चार साल से बन ही रही है यानी मोदी सरकार के 5 साल में यह बिल्डिंग पूरी नहीं हो सकी। इन्हें पूर्व सरकारों द्वारा किये गये कामों पर ही नारियल फोड़ने आते हैं। 15 अगस्त 2014 को मंझावली गांव के निकट यमुना पुल को 2 साल में बना कर चालू करने वाले वायदे का हश्र तो जनता के सामने है ही।

इस सब के अलावा खट्टर जी आजकल यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी 'खोलने' पर जुटे हैं। स्कूल कॉलेज तो चला नहीं पा रहे यूनिवर्सिटी खोलने के शिगूफे छोड़े जा रहे हैं। रोहतक स्थित मैडिकल यूनिवर्सिटी चलाने को तो पैसे हैं नहीं, एक और मैडिकल यूनिवर्सिटी कुटेल (करनाल) में बनाने की घोषणा कर दी। विदित है कि रोहतक वाली यूनिवर्सिटी में कोई रेगुलर स्टाफ भर्ती नहीं किया गया है, केवल रिटायर्ड कर्मचारियों से ही काम को घसीटा जा रहा है। उनके वेतन का खर्चा भी मैडिकल छात्रों एवं कॉलेजों पर जुर्माने लगा-लगा कर पूरा किया जा रहा है।

पिछले चार साल से पृथला के निकट दूधौला गांव में कौशल यूनिवर्सिटी का दाव चलाया जा रहा था जिसकी अभी पिछले दिनों आधारशिला रखी गयी है, यूनिवर्सिटी कब चालू होगी 'राम' जाने। अब एक स्पोर्टस (खेलकूद) यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान भी खट्टर जी ने कर दिया है। इनके पास पहले से मौजूद राई का स्पोर्ट्स स्कूल तो ठीक से ढंग से चल नहीं रहा। वहां तरह-तरह के घोटालों के आरोप एक मंत्री दूसरे मंत्री पर लगा रहे है। प्रिंसिपल के पद पर आईपीएस अधिकारी को नियुक्त करना पड़ता है। बीते 10 वर्षों में इस स्कूल के किसी खिलाड़ी ने कोई मैडल जीता हो, सुनने में नहीं आया जबकि राज्य के कितने ही खिलाड़ी, अन्य स्कूलों से पढ़कर, बड़े-बड़े मैडल प्राप्त कर रहे हैं।

दरअसल खट्टर ने यूनिवर्सिटी का नाम सुन लिया जो सुनने व सुनाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिये वे आये दिन कहीं न कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी को खोलने की घोषणा कर मारते हैं। वैसे भी घोषणा करने में जाता भी क्या है। यह कोई एफि डेविट (शपथ पत्र) तो है नहीं जिसके झूठा पाये जाने पर सजा हो सकती है। इसलिये जितना झूठ बोला जा सके बोलते रहना चाहिये। हर जिले में मैडिकल कॉलेज खोलने का दावा भी ऐसा ही एक बड़ा झूठ है। जिलों में मौजूद अस्पताल तो ठीक से चला नहीं पा रहे, मैडिकल कॉलेज खोलेंगे ये झूठ के पकौड़े तलने वाले।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150

IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
5. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
6. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
7. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**

गतांक की चीर-फ़ाड़

चौकीदार ही चोर है!

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मजदूर मोर्चा के 10-16 फ़रवरी 2019 के अंक में रफाल विमान खरीदने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)की रिपोर्ट जो इस समय फाइनल नहीं हुई थी का हवाला देकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने अनुकूल निर्णय करवाकर आशा की थी कि इससे विवाद शांत हो जायेगा। परन्तु 'द हिन्दू' में छपी प्रख्यात पत्रकार संपादक एन.राम की रिपोर्ट ने इस विवाद को और गरमा दिया है। इस सौदे से संबंधित रक्षा मंत्रालय के कई दस्तावेज पर आधारित रिपोर्ट 'द हिन्दू' में छपी है।

सरकार रफाल विमान को 9 प्रतिशत सस्ते दर पर खरीदने का दावा कर रही है, दरअसल वह जनता को भ्रमित कर रही है। फ्रांस की दस्सो कंपनी ने बेशक साधारण विमान की कीमत पर 9 प्रतिशत की छूट दी थी, लेकिन सुसज्जित विमान की कीमत 25 मिलियन यूरो बढ़ा दी और पहले के फोलो ऑन क्लाज को हटा दिया। इस प्रकार 36 रफाल विमानों को 41-42 प्रतिशत अधिक दाम पर खरीदा गया, जिसका 'झूठ के आसमान में, रफाल की कीमतों का उड़ता सच' में खुलासा किया गया है।

राज्यसभा में पेश कैग की रिपोर्ट के अनुसार यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार ने 2.86 प्रतिशत कम दाम पर रफाल करार किया था, परन्तु कैग ने कीमत का कोई जिक्र नहीं किया। सरकार ने दस्सो से एग्रीमैंट वैल्यू की 25 प्रतिशत बैंकिंग और परफोर्मेंस गारंटी नहीं ली। यह गारंटी न लेने से भारत को आर्थिक नुकसान हुआ जबकि गारंटी न देने से दस्सो को बची रकम का फायदा हुआ।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय में डिप्टी सैक्रेटरी एस.के. शर्मा ने 24 नवम्बर 2015 को नोट लिखा कि राफेल पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की समानांतर बातचीत से रक्षा मंत्रालय और वार्ताकारों की भारतीय टीम का पक्ष कमजोर हुआ है तथा तत्कालीन रक्षा सचिव जी.मोहन कुमार ने लिखा कि पीएमओ को समानांतर बातचीत से बचना चाहिए। भारतीय टीम प्रमुख एयर मार्शल, रिटायर्ड एसबीपी सिन्हा ने सफाई देते हुए कहा कि कोई समानांतर सौदेबाजी नहीं हुई थी तथा मोहन कुमार ने सफाई में कहा कि पीएमओ ने कोई समानांतर बातचीत नहीं की और मामला राफेल की कीमत से नहीं गारंटी के बारे में था।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उक्त रिपोर्ट को अधूरी बताया तो द हिन्दू ने रफाल सौदे पर एक अन्य पूरी रिपोर्ट छाप दी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और फ्रांस के बीच 7.5 बिलियन यूरो में किए गए राफेल सौदे में भारत सरकार ने फ्रांस की दो कंपनियों दास्सो और एमबीडीए फ्रांस को बड़ी रियायतें दी थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा मंत्रालयों की मंत्री मंडलीय समिति की 2016 में हुई बैठक में भ्रष्टाचार विरोधी जुर्माने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों और एस्क्रो एकाउन्ट के जरिये भुगतान करने की शर्तो को हटाया गया था। जबकि हर रक्षा सौदे में 2013 में निर्धारित की गई रक्षा खरीद प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए था। रक्षा मंत्रालय के वित्तीय अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि सीधा कंपनियों को पैसा देने की बजाये एस्क्रो एकाउंट में पैसे रखे जायें। यह खाता फ्रांस सरकार का हो और वह तभी भुगतान करे जब दस्सो सारी शर्तो को पूरा करते हुए आपूर्ति करे। लेकिन इन सुझावों को नजर अंदाज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कानून मंत्रालय की सलाह के बावजूद सरकार ने फ्रांस सरकार से सॉवरेन गारंटी भी नहीं ली।

मोदी सरकार बार-बार कहती है कि रफाल सौदे में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ लेकिन सरकार जवाबदेह है कि रफाल करार की शर्तो में भ्रष्टाचार होने पर कार्रवाई के प्रावधान को क्यों हटाया गया तथा दस्सों कंपनी से बैंकिंग और परफार्मेन्स गारंटी व फ्रांस सरकार से सॉवरेन गारंटी क्यों नहीं ली ?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के समय जनता से वायदा किया था कि प्रतिवर्ष पांच करोड़ रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे लेकिन उनके कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मोदीजी रैलियों में शिक्षा व रोजगार के मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहे। मोदी सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़ों को भी दबाने की कोशिश की, परन्तु '45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़ों को भी दबाने की कोशिश की, परन्तु '45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े को सरकार ने छुपाना चाहा लेकिन पत्रकार ने सामाना ला दिया' में बेरोजगारी की दशा का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) के श्रम शक्ति सर्वे के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1 प्रतिशत हो गई थी जो 45 साल में सबसे अधिक है। सैंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकॉनामी (सीएमआईई) के अनुसार बेरोजगारी की दर 9 प्रतिशत से भी ज्यादा है जो कि अति है। बेरोजगारी की इस भयावह दशा से स्पष्ट है कि सरकार की आर्थिक नीतियां फेल हो चुकी हैं। बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मीडिया के जरिए धार्मिक मसलों का बवंडर पैदा किया जा रहा है।

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संघ परिवार व भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश में हिन्दू राष्ट्रवाद व साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाकर ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका के खुफिया प्रमुख डान कोट्स की अमेरिकी संसद में पेश रिपोर्ट में मोदी के कार्यकाल में भाजपा शासित राज्यों में भाजपा की साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की नीतियों की 'लोकसभा चुनाव से पहले भारत में हो सकती है साम्प्रदायिक हिंसा में समीक्षा की गई है। भाजपा शासित राज्यों में भाजपा के नेता पार्टी के समर्थकों को जोड़ने के लिए हिन्दू राष्ट्रवादी अभियान चलाकर छिटपुट हिंसा भड़काते रहते हैं, जिससे साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाता है।

न्यायपालिका के न्यायाधीशों विशेषकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संदेह से परे होना चाहिए। लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट में हुई कुछ हाल की घटनाएं जैसे राम जन्मभूमि के मामले की सुनवाई में असाधारण देरी, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तबादले को रद्द करना, दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना को उनसे वरिष्ठ जजों को पीछे छोड़कर प्रोमोशन देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनान आदि से मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई। 'जस्टिस मार्कंडेय काटजू के सीजेआई रंजन गोगोई के चार सवाल' के जरिये जस्टिस काटजू ने सीजेआई गोगाई से प्रासंगिक प्रश्न पूछे हैं।

'मोदी राज में बैंक अधिकारी बढ़ते एनपीए से ही नहीं अपनी घटती साख से भी जूझ रहे' में सरकारी बैंकों व बैंक कर्मियों की दशा, बैंकों का आपस में विलय की नीति, नोटबंदी के असर तथा मुद्रा लोन और स्टैंड अप इंडिया लोकन का सटीक विश्लेषण किया गया है। बैंकों के आपस में विलय से बैंकों के मजबूत होने के वित्तमंत्री अरूण जेटली के दावे के झूठ का पर्दाफाश करते हुए बताया गया कि विलय से बैंक मजबूत नहीं होंगे, उल्टा ये सरकार की साजिश है कि जिससे कि बैंक सैक्टर का निजीकरण किया जा सके। मुद्रा लोन व स्टैंड अप इंडिया जैसे लोन राजनीतिक हैं जो सिर्फ रानजीतिक सिफारिशी को मिलते हैं और लौटते कभी नहीं। बेरोजगारी के कारण एजुकेशन लोन भी एनपीए होते जा रहे हैं जिसकी 'रोजगार नहीं तो एजुकेशन लोन कैसे चुकाये?' में विवेचना की गई है।

वैदिक शिक्षा के साथ क्रांतिकारियों की स्थली गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की 217 एकड़ भूमि से लूटपाट करने की मंशा से रोहतक की हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा वहां अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है। सरकार, नेता, पुलिस व दबंगों के गठजोड़ से जालसाजों ने रजिस्ट्रार सोसयटीज हरियाणा से गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ प्रबंध समिति का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का नोटिस यह कहकर जारी करवा दिया कि इस समिति का मर्जर हो गया था जिसका अब कोई वजूद ही नहीं है। गौरतलब है कि समिति के चुनाव हर तीन साल पर बाकायदा होते रहे हैं जिसकी सूचना जिला रजिस्ट्रार सोसायटीज को नियमित रूप से दी जाती रही है और चुनावों की मंजूरी 22.12.2018 को भी की हुई है। पूरे प्रकरण का 'ताकि हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा बेरोक टोक 217 एकड़ की लूट पचा सकै। गर्वनर के इशारे पर गुरूकुल इन्द्रप्रस्थ प्रबंध समिति को भंग करने का नोटिस' में पूरा भंडाफेड़ किया गया है।

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण बैंकों की दशा पर 'बैंक-जमा भुगतान सैटिंग' तथा मोदी सरकार द्वारा लघु व सीमांत किसानों को 500 रुपया महीना तथा यूपी की योगी सरकार द्वारा साधु संतों को 2000 रुपया महीना पेंशन देने पर 'किसान को 500 रुपए साधु को 2000 हजार रुपए महीना मिलेंगे - पहले मैं किसान था। कार्टूनों द्वारा मोदी सरकार व योगी सरकार की नीतियों पर उपयुक्त तंज कसा गया है।